(c) the places selected by the railways for construction of such houses ;

(d) the places where land has already been acquired ; and

(e) the cost of various categories of houses/flats to be constructed and the facilities for loans to be provided by the railways/other organisations ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. K. JAFFER SHARIEF) : (a) Yes, Sir.

(b) About 47,000 beneficiaries have registered themselves as primary members of Indian Railway Welfare Organisation (IRWO).

(c) IRWO has tentatively selected 70 places which include Zonal Railway Headquarters, Divisional Railway Headquarters, State Capitals and other important towns.

(d) Land has been acquired at NOIDA, Gorakhpur, Gurgaon, Calcutta, Madras, Hyderabad, Panchkula, Meerut, Indirapuram, Jaipur and Bombay.

(e) The estimated cost of houses/flats various from Rs. 85,000 to Rs. 6.5 lakh depending on the type of houses, cost of land and technical specifications.

Serving employees can avail of the facility of House Building Advance as per extant rules. In addition, IRWO is co-ordinating with various agencies for getting loans for all the allottees.

"एड्स" तथा अन्धेपन की बीमारी के नियंत्रण के लिए महाराष्ट्र को वित्तीय सहायता

*34. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य में "एडस" तथा अंधेपन की बीमारी को नियंत्रित करने के लिये वित्तीय सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां तो सरकार इन दो योजनाओं के लिये महाराष्ट्र सरकार को क्या सहायता उपलब्ध कराने का विचार रखती है ;

(ग) क्या सरकार "एड्स" के रोगियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुये ऐसे रोगियों के लिये मुंबई में एक अस्पताल खोलनें का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम०एल० फोतेदार) : (क) एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिये अप्रैल 1987 से एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का कार्यान्वियन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निगरानी रखने, रक्त सुरक्षा को प्रोत्साहन देने एवं एड्स रोगियों के उपचार के लिये सुविधायें विकसित करने के लिये महाराष्ट्र सरकार को सहायता प्रदान की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी सहायता प्राप्त की गई और 1 जनवरी 1990 से रोकथाम और नियंत्रण सम्बन्धी कार्यकलाप शुरू करने के लिये 43.54 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है।

(ख) अब एक विस्तृत राष्ट्रीय एड्स परियोजना तैयार की गई है जिसका परिव्यय 270 करोड़ रुपये है। इस परियोजना को धन की व्यवस्था के लिये विश्व बैंक को भेजा गया। बातचीत अभी हाल ही में संपन्न हुई है और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (विश्व बैंक का एक उदार ऋण सहयोगी) द्वारा 229.5 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान किये जाने की आशा है। यह परियोजना पहली अप्रैल 1992 से पांच वर्ष की अवधि में लागू की जायेगी। इस परियोजना के अन्तर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्यकलाप शुरू करने के लिये महाराष्ट्र सरकार को नकद और सामग्री के रूप में सहायता प्रदान की जायेगी:–

—कार्यक्रम प्रबंधन;
—निगरानी;
—रक्त सुरक्षा;
—सुरक्षा शिक्षा और संचार;
—यौन संचारित रोगों पर नियंत्रण;
—कंडोमों के प्रचलन को प्रोत्साहन;
—रोगी उपचर्या ।

महाराष्ट्र में केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में वृष्टिहीनता की रोकथाम संबंधी एक कार्यक्रम पहले से ही कार्यान्वित किया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सरकार को 61.83 लाख रुपये की राशि जारी की गई है

मोतियाबिंद के बकाया रोगियों का इलाज करने पर ध्यान देने के लिये नेत्र परिचर्या सेवा को सुदृढ़ करने के लिये एक विस्तृत परियोजना विश्व बैंक को मूल्यांकन के लिये भेज दी गई है।

(ग) और (घ) बम्बई के जे०जे० अस्पताल में एड्स रोगियों के इलाज के लिये सुविधायें उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय एड्स परियोजना के तहत, जिला अस्पतालों सहित देश के सभी प्रमुख अस्पतालों में एड्स रोगियों के इलाज के लिये सुविधायें विकसित की जायेंगी।

एड्स रोगियों के इलाज के लिये एक अलग अस्पताल खोलना संभव नहीं होगा क्योंकि एड्स रोगियों के लिए अनेक विषयों की विशेषज्ञ परिचर्या की आवश्यकता होगी जो केवल जनरल अस्पतालों में ही उपलब्ध हो सकेगी

Purchase of Electric Locomotives

*35. SHRI CHATURANAN MISHRA :

SHRI GURUDAS DAS GUPTA :

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have placed an order worth US$ 200 million for the outright pruchase of electric locomotives from the Swedish-German firm, ASEA-Brown Boveri (ABB) ; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. K. JAFFER SHARIEF) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Concept of environment courts

*36. SHRI B.K. HARIPRASAD;
SHRI PRABHAKAR B. KORE:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government had floated the concept of Environment Courts, and if so, what are the main features thereof ;

(b) what is the present status of the proposed legislation in this regard ; and

(c) whether there is any proposal to involve the various Non-Governmental Organisation engaged in the Eco-health aspects such as South Solidarity which is actively championing this cause in the sub-continent ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH) : (a) and (b) A proposal to set up an Environment Tribunal to provide strict liability for damages arising out of any accident involving hazardous substances and also to provide for compensation and interim relief to the affected persons is under the consideration of Government.

(c) Access to the tribunals by aggrieved persons and representative bodies in the field of environment has been proposed.

Import of mobile vans for rural health scheme

*37. SHRI GURUDAS DAS GUPTA:
SHRI CHATURANAN MISHRA :

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a fleet of 300 rural health service mobile vans specially imported from Britain to promote rural health all over the country, are now lying unused in the court yards of various Medical Colleges in the country ;

(b) Whether Government have given up the Re-orientation of Medical Education (ROME) Scheme ;

(c) if so, when was the scheme launched and when was it given up ;

(d) what is the total expenditure incurred thereon and the reasons for giving up the scheme ; and

(e) what is the reason for not taking any step to utilise the equipment imported for the purpose for any other schemes beneficial to the common people ?